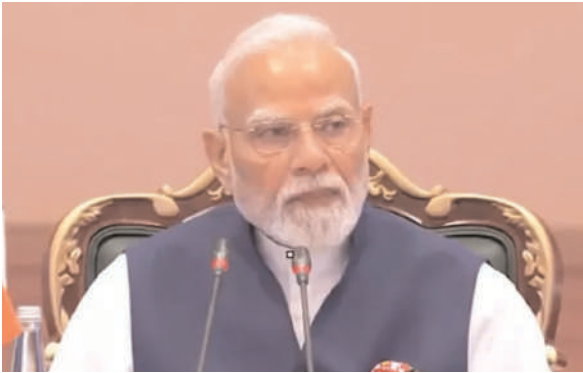




ब्रिक्स समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र, दुनिया को बड़ी अपेक्षाएं: प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में सभी देशों की सक्रिय भागीदारी और महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चचाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में अपनाई गई ह्नाई दिल्ली घोषणाह्ना साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग को स्पष्ट दिशा देगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में हुई चचाओं और तय परिणामों



को समयबद्ध कार्रवाई और अंतिम स्तर तक प्रभाव से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा, ह्नाब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है। दुनिया अब हमसे केवल

विचारों और प्रतिबद्धताओं की ही नहीं बल्कि ठोस परिणामों की भी अपेक्षा करती है। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से हम निश्चित रूप से इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे ह्ना

उन्होंने ब्रिक्स के अगले मेजबान के रूप में चीन को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के ढांचे को केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि जमीन पर वास्तविक बदलाव और प्रभाव दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देश मिलकर इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों के विचारों और सुझावों ने सहयोग को व्यापक और गहरा बनाने में योगदान दिया है। उनकी उपस्थिति ब्रिक्स की बढ़ती प्रासंगिकता, खुलेपन और समावेशिता को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अफ्रीकी महाद्वीप के तीन प्रमुख नेता नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा मुस्ताफा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष व बुरुंडी के राष्ट्रपति एवारैस्टे नदाइशिमिये के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग तथा 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को मजबूती से उठाने पर सहमति बनी। साथ ही भारत-अफ्रीकी संघ साझेदारी को नई गति देने और चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएफएस-क्व) के जल्द आयोजन पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा मुस्ताफा के साथ वार्ता में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा साझेदारी, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने अधिक प्रतिनिधि, समावेशी और बहुदुर्घीय वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए बहुपक्षीय मंचों पर तालमेल बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। नाइजीरियाई उपराष्ट्रपति ने देश में क्षमता निर्माण और आर्थिक विकास में भारत के योगदान की सराहना की। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और ऐतिहासिक संबंधों व सांस्कृतिक निकटता पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर करीबी समन्वय बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीतों के सफल पुनर्वास के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका को 'इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस' (आईबीसीए) में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके अलावा, अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष एवं बुरुंडी के राष्ट्रपति एवारैस्टे नदाइशिमिये के साथ बैठक में वर्ष 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने की ऐतिहासिक पहल को याद किया गया। दोनों नेताओं ने भारत-अफ्रीकी संघ साझेदारी को 'ग्लोबल साउथ' का प्रमुख स्तंभ बताते हुए परस्पर सुविधाजनक तिथि पर चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के शीघ्र आयोजन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इबोला प्रकोप से निपटने में एयू के नेतृत्व की सराहना की, जबकि एयू अध्यक्ष ने प्रकोप की रोकथाम के लिए अफ्रीका सीडीपी को भारत द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही भारत-बुरुंडी संबंधों के तहत आर्थिक सहयोग, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण की समीक्षा की गई।



ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक सुधार और ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व पर जोर

नई दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रविवार को दो दिनों की गहन चचाओं और बैठकों के बाद सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में वैश्विक सुधार और ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व देने पर जोर रहा। इस दौरान भारत के इस केंद्रीय प्रस्ताव पर व्यापक सहमति बनी कि ब्रिक्स को केवल घोषणात्मक होने के बजाय व्यावहारिक, कार्रवाई योग्य और जन-केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा ब्रिक्स में स्पष्ट शब्दों में आतंकवाद की निंदा की गई और स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और आपदा से निपटने की क्षमता जैसे क्षेत्रों में सहयोग पक्का किया गया। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता

का उपयोग भागीदारी को सीमित करने के बजाय व्यापक बनाने के लिए किया। भारत की अध्यक्षता परिणामों पर केंद्रित रही। शिखर सम्मेलन ने चार प्राथमिकता स्तंभों में परिणामों के महत्वपूर्ण पैकेज को मंजूरी दी। विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में 50 से अधिक ठोस परिणाम सामने आए। ब्रिक्स में दुर्लभ खनिजों को भी सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा में ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखकर विचार विमर्श किया गया। इसी को प्रधानमंत्री ने अपने हस्तक्षेप में कहा ह्नाहमें 'ग्लोबल साउथ की उम्मीद के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए और तभी हम उन उम्मीदों को पूरा

करने के लिए उन्हें वैश्विक मंच पर असरदार तरीके से बता सकते हैं ह्ना ब्रिक्स शिखर वार्ता के समापन के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) और ब्रिक्स के शेरपा सुधाकर दलेला, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और मल्टीलेटरल इकोनामिक रिलेशंस के जॉइंट सेक्रेटरी शंभू हक्की मौजूद रहे। शेरपा सुधाकर दलेला ने बताया कि समावेशी विकास पर प्रधानमंत्री के केंद्रीय संदेश में कहा गया कि ब्रिक्स में विकसित समाधान केवल ब्रिक्स तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। इन्हें वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना और सुलभ बनाना

आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स के तीसरे दशक में प्रवेश करने के साथ ही, दुनिया उससे न केवल विचारों और प्रतिबद्धताओं की, बल्कि ठोस परिणामों की भी अपेक्षा करती है। दलेला ने कहा कि भारत ने अध्यक्षता के दौरान बातचीत से इतर ब्रिक्स को लोगों, खासकर युवाओं से जोड़ने पर जोर दिया। गांधीनगर में युवा शिखर सम्मेलन और युवा परिषद आयोजित हुई। महिला सशक्तीकरण के लिए कार्यसमूह और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का डिजिटल संग्रह बनाया गया। खेलों के जरिए जन-जन संपर्क बढ़ाने के लिए खेल तकनीक कार्यसमूह, ब्रिक्स रन और पारंपरिक खेलों का आयोजन हुआ।

गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और शुभाशंख का प्रतीक बताते हुए लोगों के जीवन में सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गणेश चतुर्थी का पर्व जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लेकर आता है। यह पवित्र पर्व लोगों को नए संकल्पों के साथ प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

विधायक के बेटे के अपहरण और मारपीट मामले में पांच आरोपित कोलकाता से गिरफ्तार

रांची। रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर से चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ कुमार के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में शामिल पांच आरोपितों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रौनक सिंह राजपूत, प्रकाश गुप्ता, आयुष कुमार, प्रीतम और ज्ञानदीप के रूप में हुई है। घटना सात सितंबर की है। पुलिस के अनुसार, विधायक के बेटे सौरभ कुमार यूनिवर्सिटी गेट के पास अपने दोस्तों अमरदीप दुबे, अनमोल और रविशंकर के साथ खड़े थे। इसी

दौरान अमरदीप की किसी बात को लेकर जूनियर छात्र लक्की राज से विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद लक्की राज ने फोन कर कुछ बाहरी युवकों को मौके पर बुला लिया। कुछ देर बाद दो काले रंग की स्कॉर्पियो से करीब 10-12 युवक वहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। सौरभ की शिकायत के अनुसार, आरोपितों ने उनके दोस्त अनमोल को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और सौरभ को जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर वहां से ले गए। सौरभ ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि चलती गाड़ी में उनके साथ मारपीट की गई और उनका गला दबाने की कोशिश की गई। आरोपितों ने उनका मोबाइल

फोन और करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन भी छीन ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने घटना के करीब दो घंटे के भीतर सौरभ कुमार को सकुशल बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की। जांच के क्रम में पांच आरोपितों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य लोगों और पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

चेंबर चुनाव में टीम तुलसी पटेल ने मारी बाजी, 13-8 से जीत

रांची। झारखंड चेंबर की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के रविवार को हुए चुनाव में टीम तुलसी पटेल ने 13-8 से जीत दर्ज की। टीम तुलसी पटेल के 13 प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि टीम मुकेश अग्रवाल के आठ प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। तीसरी टीम पी-21 का खाता नहीं खुल सका। इस तरह 21 सदस्यीय कार्यकारिणी में तुलसी पटेल की टीम को स्पष्ट बहुमत मिला है। अध्यक्ष पद के लिए तुलसी पटेल के नाम की आधिकारिक घोषणा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। चुनाव परिणाम की घोषणा चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर और पवन शर्मा ने की। चेंबर के कुल 42.14 मतदाताओं में से



मुकेश अग्रवाल को सर्वाधिक 1827 वोट
 मतगणना में टीम मुकेश अग्रवाल के मुकेश अग्रवाल सर्वाधिक 1827 वोट हासिल कर पहले स्थान पर रहे। डॉ अभिषेक रामायीन 1742 वोट के साथ दूसरे, प्रवीण लोहिया 1725 वोट के साथ तीसरे, तुलसी पटेल 1622 वोट के साथ चौथे और विनीता सिंघानिया 1597 वोट के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

व्यापारियों के विश्वास की जीत : तुलसी पटेल
 जीत के बाद तुलसी पटेल ने कहा कि यह व्यापारियों और उद्योगियों के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा, सरल कारोबारी व्यवस्था, कानून-व्यवस्था में सुधार और आधारभूत संरचना को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी।

ये 21 प्रत्याशी जीते
 मुकेश अग्रवाल 1827, डॉ अभिषेक रामायीन 1742, प्रवीण लोहिया 1725, तुलसी पटेल 1622, विनीता सिंघानिया 1597, ज्योति कुमार 1535, राम बांगड 1506, मनीष जैन 1497, नवजोत अलम 1496, निधि झुनझुनवाला 1450, आस्था किरण 1441, अमित अग्रवाल 1424, राहुल साहू 1418, रोहित पोद्दार 1384, अनिल अग्रवाल 1360, अमित शर्मा 1348, रोहित अग्रवाल 1347, अमित किशोर अग्रवाल 1344, विकास विजयवर्गीय 1305, मीनिका गौयन्का 1300 और पूजा दादा 1288 वोट के साथ विजयी रही। प्रत्याशियों ने भी चुनाव लड़ा, जिनमें छह ने जीत दर्ज की। वहीं, मनीष जैन ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर देशभर में चलेगा सेवा संकल्प अभियान: अमित शाह

एजेंसी मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। नेशन फस्ट की भावना, जन सेवा ही प्रभु सेवा के मंत्र और 2047 तक जनभागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए आयोजित किए जा रहे इस अभियान में भाजपा, उसके सहयोगी दलों, एनडीए परिवार, स्वयंसेवी



संस्थाओं और आम लोगों की भागीदारी होगी। अमित शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, जबकि 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकर बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। इसके तहत देशभर में 12 प्रमुख कार्यक्रमों के साथ बूथ, मंडल और जिला स्तर पर सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बड़ी उपलब्धि है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान को देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिले, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के हर एक बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। इसका तहत देशभर में 12 प्रमुख कार्यक्रमों के साथ बूथ, मंडल और जिला स्तर पर सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने स्वयं को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत किया और संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, देश की आर्थिक मजबूती, सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश की 140 करोड़ जनता के सामने रखा है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, उनकी उपलब्धियों, लक्ष्यों और आने वाले समय के संकल्पों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सेवा दिवस के तहत रक्तदान शिविर,

दीप प्रज्वलन और नागरिकों के सम्मान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के लिए जनता की ओर से आभार व्यक्त करने के अवसर के रूप में मनाया जाएगा। माई ड्रीम इंडिया थीम पर देशभर में पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें बच्चे, किशोर और युवा हिस्सा लेंगे। आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान बच्चों और माताओं से जुड़ी पोषण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। सेवा कथा कार्यक्रम में उन लोगों की वास्तविक कहानियां सामने लाई जाएंगी, जिनके जीवन में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण सकारात्मक

बदलाव आया है। सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न गांवों और क्षेत्रों को जोड़ है, प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के लिए आभार व्यक्त करना और लोगों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ है। वडनगर-वाराणसी सेवा यात्रा के तहत वडनगर से वाराणसी और वाराणसी से वडनगर के लिए 10-10 समूह बनाए जाएंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य विभिन्न पवित्र नदियों के जल से वडनगर स्थित हाटकेश्वर महादेव और वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करना होगा। यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों पर सेवा से जुड़े 25 विषयों पर गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

झारखंड में 17 सितंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, येलो अलर्ट

रांची। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 17 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर रविवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त की तरह सितंबर में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। इससे राज्य में बारिश की कमी में काफी सुधार हुआ है। एक जून से 13 सितंबर तक झारखंड में 869.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से महज चार प्रतिशत कम है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति सामान्य मानी जाती है। पिछले 24 घंटों के दौरान जामताड़ा जिले के नारायणपुर में सबसे अधिक 31.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में

राज्य का सर्वाधिक तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लातेहार में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। दोपहर बाद आसमान में बादल छाए रहे। दिनांश गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। रांची में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के प्रमुख शहरों में जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 25.2 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 33.2 और न्यूनतम 24.5 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 32.1 और न्यूनतम 25.2 डिग्री तथा चाईबासा में अधिकतम 32.4 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

नवजात को निजी अस्पताल ने बनाया बंधक, पुलिस ने छुड़ाया

गोरखपुर (एजेंसी)। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए रेफर की गई एक नवजात बच्ची को एंबुलेंस चालक ने धोखे से फातिमा बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचा दिया। स्वजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल ने पहले 96 हजार रुपये वसूले और फिर बच्ची को बंधक बनाकर डिस्चार्ज के लिए 90 हजार रुपये और मांगे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अतिरिक्त 30 हजार रुपये लेकर बच्ची को छोड़ा गया। कुशीनगर के कसया स्थित वरदान अस्पताल में 29 अगस्त को जन्मी इस बच्ची को सांस लेने में दिक्कत थी। प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 5 सितंबर को उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। बच्ची के बाबा अर्जुन कुशवाहा ने बताया कि इसी दौरान एक निजी एंबुलेंस चालक ने उन्हें गुमराह किया और बेहतर इलाज का झांसा देकर शाहपुर के फातिमा बाईपास स्थित एकता मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया। स्वजनों के मुताबिक, 5 सितंबर से बच्ची का उपचार इसी अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान इलाज और दवा के नाम पर उनसे 96 हजार रुपये जमा करा लिए गए। जब उन्होंने बच्ची को डिस्चार्ज कर बीआरडी ले जाने का अनुरोध किया, तो अस्पताल प्रबंधन ने 90 हजार रुपये और जमा करने को कहा। रकम न देने पर बच्ची को बंधक बनाए रखा गया। परेशान स्वजनों ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शाहपुर थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया। शाहपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि समझाने-बुझाने के बाद 30 हजार रुपये और लेकर नवजात को डिस्चार्ज कराया गया। हालांकि, अस्पताल संचालक मैनुईन ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि केवल उपचार में लगे खर्च की ही धनराशि ली गई है।

निखिल कोचिंग संचालक ने मांगी सुरक्षा, कहा- खान सर से खतरा

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजधानी पटना के मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर उर्फ फेजल खान एक बार फिर गंभीर विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। पहले रोशन आनंद के साथ उनके विवाद ने सुर्खियां बटोरी थीं, और अब करीब एक महीने पहले उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने खान सर के खिलाफ पटना के पीरबहेर थाने में सुरक्षा को लेकर एक आवेदन दिया था, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में निखिल कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर निखिल कुमार ने उस लड़की का खुलकर समर्थन किया है, जिसके बाद उन्होंने खान सर के कथित गुणों द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है [निखिल कुमार ने इस संबंध में पटना सिटी एसडीपीओ और पटना एसएसपी को एक लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा है कि उनके गुणों द्वारा उनकी रेकी (जासूसी) की जा रही है और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है।

पश्चिम बंगाल में बिना पंजीयन कर चल रहे 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में बिना पंजीकरण या मान्यता के संचालित हो रहे मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के 22 जिलों और कोलकाता में कराए गए सर्वेक्षण में 2396 मदरसे ऐसे पाए गए हैं, जिनके पास सरकारी पंजीकरण या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड की मंजूरी नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से कराए गए इस सर्वेक्षण के आधार पर पहले चरण में 252 मदरसों को तत्काल बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के मुताबिक सर्वेक्षण में कुल 2,132 मदरसे ऐसे पाए गए जो जरूरी पंजीकरण या मान्यता के साथ संचालित हो रहे हैं। वहीं, जिला प्रशासन की रिपोर्ट में 2,396 संस्थानों के पास जरूरी पंजीकरण या सरकारी बोर्ड से संबद्धता नहीं होने की जानकारी सामने आई है। सत्यापन के बाद मदरसा शिक्षा निदेशालय ने 252 संस्थानों को संचालन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। इन नोटिस की प्रतियां संबंधित जिलाधिकारियों को भी भेजी गई हैं। जिलाधिकारियों को यह तय करने के लिए कहा गया है कि संबंधित संस्थानों का संचालन बंद हो। इसके अलावा 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यदि वे अपनी वैधता साबित करने में विफल रहते हैं तो कानून की हडताल उनके खिलाफ भी बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है।

सागर शराब कांड में 2 की और मौत, मृतक संख्या 36 हुई

सागर (एजेंसी)। सागर जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांड में उपचार के दौरान दो और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही जहरीली शराब से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अवैध शराब के निर्माण और बिक्री से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। वहीं, अस्पतालों में भर्ती अन्य प्रभावित लोगों के उपचार में भी निगरानी रखी जा रही है। इस घटना ने अवैध शराब के कारोबार और प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने की मांग की है।

आतंकवाद से लेकर वैश्विक सुधार तक ब्रिक्स देशों का साझा रुख

ब्रिक्स घोषणापत्र में भारत की कूटनीतिक जीत

नई दिल्ली, एजेंसी। यहां आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणापत्र जारी किया गया, जिसने आतंकवाद, वैश्विक शासन सुधार और मध्य-पूर्व संकट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य देशों का साझा रुख प्रस्तुत किया। इस घोषणापत्र को भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर साझा सहमति बनाना कठिन माना जा रहा था।घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के पहलमगम में अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। ब्रिक्स ने देश-समर्थित सीमा पर आतंकवाद, इसकी फंडिंग और आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। चीन और रूस जैसे देशों की मौजूदगी में किसी विशिष्ट आतंकी घटना का नाम शामिल करना और सीमा पर आतंकवाद पर सीधा रुख अपनाना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, जो आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करता है।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की मांग को दोहराते हुए ब्रिक्स देशों ने इसे अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। चीन और रूस ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र



में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका और आकांक्षाओं के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। चीन का पहले यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करना और अब इस पर सहमति जताना, भारत की दीर्घकालिक कोशिशों को रणनीतिक बल प्रदान करता है। गाजा संकट पर गहरे चिंता व्यक्त करते हुए घोषणापत्र में बिना बाधा मानवीय सहायता पहुंचाने और स्थायी युद्धविराम की मांग की गई। घोषणापत्र में एकरतफा टैरिफ, व्यापार बाधाओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना लगाए

जाने वाले आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध किया गया। यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे ग्रीन-टैक्स उपायों को संरक्षणवाद करार दिया गया। इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन में तत्काल सुधार और उसके ठप पड़े विवाद निपटान तंत्र की बहाली की मांग की, जो नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। सदस्य देशों ने आपस में स्थानीय मुद्दों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और भुगतान प्रणालियों के बीच इंटर-कनेक्शन विकसित करने पर सहमति

जताई, जिससे अमेरिकी डॉलर पर वैश्विक निर्भरता कम होगी। भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी आईएफएससी में ब्रिक्स रिस্ক लेब स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शासन पर भारत की पहल एआई इपैक्ट समिट की सराहना की गई, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में रखता है। घोषणापत्र में शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया।

ब्रिक्स में विशेषज्ञों ने कहा- भारत बना वैश्विक डिजिटल और एआई का केंद्र

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने भारत की डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक भूमिका की जमकर सराहना की। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत तेजी से एक वैश्विक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेषकर केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसके चलते ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी वाले वर्षों में रोजगार और काम करने के तरीकों में बड़े बदलाव लाएगा। आदान-प्रदान की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने सरकारों और उद्योगों को इस उन्होंने भारत के विशिष्ट डिजिटल भूगतावन मॉडल, विशेषकर यूपीआई, जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की कां भी विश्व के लिए एक अनुरूपणीय और वित्तीय समावेशन का एक प्रतीक बना गया है। इस अवसर पर मिश्र के एआई विशेषज्ञ अहमद गमाल ने ब्रिक्स को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए तकनीकी सहयोग और नवाचार का

एक साझा मंच बताया। उन्होंने भारत और मिश्र के बीच एआई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला, जिससे भविष्य में संयुक्त परियोजनाओं और ज्ञान साझा करने का मजबूत आधार तैयार हो सकता है। गमाल ने यह भी कहा कि एजेंटिक एआई का उभरता दौर, आने वाले वर्षों में रोजगार और काम करने के तरीकों में बड़े बदलाव लाएगा। उन्होंने सरकारों और उद्योगों को इस बदलती तकनीक को समझकर इसका भूगतावन मॉडल, विशेषकर यूपीआई, जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की कां भी विश्व के लिए एक अनुरूपणीय और वित्तीय समावेशन का एक प्रतीक बना गया है। इस अवसर पर मिश्र के एआई विशेषज्ञ अहमद गमाल ने ब्रिक्स को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए तकनीकी सहयोग और नवाचार का प्रोत्साहित किया।

सवालों पर बोले दीपके- मुझे सीएम समझ रहे हैं तो इस्तीफा दे देता हूं बोले- टेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा

बालाघाट, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे कांकोरच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके को शनिवार को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। आदिवासी इलाके में संक्रामक बीमारियों से बच्चों की मौतों के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे दीपके की कार को कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने घेर लिया और उनसे तीखे सवाल किए, जिसके बाद दीपके ने तंज कसते हुए कहा कि आप मुझे मुख्यमंत्री समझ रहे हैं तो मैं इस्तीफा दिए देता हूं। वायरल हुए एक वीडियो में, एक महिला इन्फ्लुएंसर खुद को बताते हुए दीपके से पूछती सुनाई दे रही है कि क्या वह लाशों पर राजनीति करने आए हैं और इतनी देर से क्षेत्र का दौरा क्यों कर रहे हैं। वीडियो में दीपके यह कहते सुने गए कि क्षेत्र का दौरा करने में हुई देरी के लिए वह माफी मांगते



हैं। महिला को यह कहते भी सुना गया, यहां अच्छी सड़क बनी है, दिखाई नहीं दे रही क्या? इस बहस के बाद अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए कहा कि वह मध्य प्रदेश के राजभवन जाकर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दे

देंगे। उनकी पार्टी, सीजेपी ने भी इसी तर्ज पर तंज कसते हुए कहा कि अभिजीत दीपके को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रश्न कर रहे

थे जैसे सूबे के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हों। दीपके बालाघाट में उन आदिवासी परिवारों से मिलने पहुंचे थे, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा बताया जा रहे मौतों के आंकड़े वास्तविकता के मुकाबले बहुत कम हैं। दीपके ने दावा किया कि आदिवासियों के सड़क पर उतरने के बाद कम से कम 86 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और अगर बच्चों की समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। स्थानीय पत्रकारों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि दूरदराज के गांव में बाहर से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समूह मौजूद था। उन्होंने आशंका जताई कि दीपके के दौर में बाधा डालने के लिए इन लोगों को किसी के कहने पर वहां भेजा गया था, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

ब्रिक्स समिट के बीच राहुल गांधी की मलेशियाई पीएम इब्राहिम से मुलाकात

-प्रियंका गांधी भी रहीं मौजूद, दोनों नेताओं ने ब्रेकफास्ट पर की बातचीत

नई दिल्ली, एजेंसी।

नई दिल्ली, (इएमएस)। दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से रविवार को मलेशियाई के प्रधानमंत्री दातों' सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा भी मौजूद रही। दोनों नेताओं की मुलाकात ब्रिक्स सम्मेलन से इतर हुई और उन्होंने साथ में नाश्ता किया। कांग्रेस पार्टी ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच हुई इस मुलाकात को भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते संबंधों के बीच अहम माना जा रहा है।



हालांकि, बैठक में किन विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इससे एक दिन पहले मलेशियाई प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी द्विपक्षीय मुलाकात की थी। ब्रिक्स से इतर हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद कहा था कि भारत और मलेशिया के अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की भी तारीफ ढांचे और प्रतिभा की आवाजजाही

जैसे नए और महत्वाकांक्षी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग, द्विपक्षीय निवेश और लोगों के बीच मजबूत होते संबंध व्यापक राणनीतिक साझेदारी को नई गति दे रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा था कि भारत और मलेशिया दोनों देशों के रिशतों की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। वहीं, द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत में अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की भी तारीफ की थी।

पांच राज्यों में आपराधिक मामलों वाले 1405 उम्मीदवारों को टिकट बांटे गए

-रिपोर्ट में खुलासा, राजनीतिक पार्टियों ने दागियों को टिकट देने की वजह नहीं बताई

नई दिल्ली,, एजेंसी। एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच राज्यों में आपराधिक मामलों वाले 1405 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। ये राज्य असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पार्टियों ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 176 उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह नहीं बताई। एडीआर ने 51 पार्टियों के 3,539 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जांच की। इनमें 1,405 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपराधिक मामले घोषित किए थे। इनमें से 1,229 प्रत्याशियों के

लिए पार्टियों ने सी-7 फॉर्म में जानकारी दी, जबकि 176 ने जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक पांचों राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवारों के सी-7 खुलासे नहीं मिले। एडीआर ने यहां 1,162 उम्मीदवारों का रिकॉर्ड देखा, जिनमें 473 ने आपराधिक मामले घोषित किए थे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 55, केरल में 27, पुडुचेरी में 12 और असम में 10 उम्मीदवारों की सी-7 जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पुडुचेरी में 112 उम्मीदवारों में से 39 ने आपराधिक मामले घोषित किए थे। इनमें सिर्फ 12 उम्मीदवारों के टिकट देने का कारण

उपलब्ध था। एडीआर ने सिर्फ सी-7 जानकारी गायब होने पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि पार्टियों की ओर से दिए गए कारणों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई उम्मीदवारों के लिए लोकप्रियता, सामाजिक कार्य, अनुभव, योग्यता और अच्छी छवि जैसे एक ही तरह के कारण बताए गए। कई मामलों में भाषा भी एक जैसी थी यानी हर उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड और योग्यता के आधार पर अलग कारण बताने के बजाय एक तय भाषा का इस्तेमाल किया गया। एडीआर ने तमिलनाडु में बीजेपी,

एआईएडीएमके, डीएमके और टीवीके के कुछ उम्मीदवारों के सी-7 फॉर्म में एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल का जिक्र किया है। इससे सवाल उठता है कि क्या उम्मीदवारों के चयन की वजहों को अलग-अलग तैयार किया गया था या सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई। एडीआर ने कहा कि रिपोर्ट चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पार्टियों की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। संभव है कि कुछ पार्टियों ने सी-7 की जानकारी किसी दूसरे जरिए से जारी की हो, जो एडीआर के रिकॉर्ड में नहीं आ पाई गई। इसलिए 191 मामलों में जानकारी नहीं मिलने को सीधे नियमों का उल्लंघन नहीं माना गया



है। इसे सार्वजनिक रिकॉर्ड में जानकारी उपलब्ध न होने के तौर पर देखा गया है।

संक्षिप्त डायरी

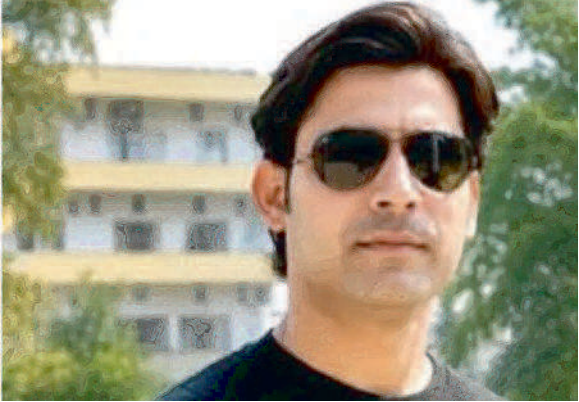
बिहार के 1.04 करोड़ लोगों को मिलेगा पीएम आवास, इन लोगों

का कट सकता है नाम, जानिए क्यों नहीं मिलेगा लाभ

पटना (एजेंसी) बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है. 1 करोड़ से अधिक लोगों की सूची तैयार है, लेकिन 40% लोगों के नाम कटने की संभावना है. अपात्रता के कड़े मापदंडों और अनुमोदन प्रक्रिया को समझें. बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत घर पाने वाले संभावित लाभुकों की प्रक्रिया आगे बढ़ गयी है. राज्य के 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार 743 लाभुकों को योजना का लाभ देने के लिए आवास सॉफ्टवेयर के जरिए प्रारूप सूची तैयार की गयी है. 11 सितंबर को 'डिलीशन मॉड्यूल' का काम पूरा कर सूची जिला लॉगिन में भेज दी गयी है. जबकि 40 फीसदी लाभुकों की प्रक्रिया आगे बढ़ गयी है. 30 सितंबर तक ग्रामसभा से सूची का अनुमोदन तैयार प्रारूप सूची को अब संबंधित ग्रामसभा के सामने रखा जायेगा. अधिकतम 20 दिनों के भीतर यानी 30 सितंबर तक ग्रामसभा से सूची का अनुमोदन कर उसे प्रखंड कार्यालय को वापस भेजना अनिवार्य होगा. इसके लिए 27 सितंबर को पंचायत विकास दिवस के अवसर पर विशेष ग्रामसभा आयोजित कर सूची के अनुमोदन की तैयारी है. समय पर ग्रामसभा नहीं हुई तो सूची स्वतः अनुमोदित निर्धारित समय-सीमा में यदि किसी पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन नहीं हो पाता है, तो संबंधित सूची स्वतः अनुमोदित मानी जायेगी. साथ ही समय पर ग्रामसभा नहीं कराने वाले संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. 31 अक्टूबर तक अंतिम प्राथमिकता सूची पर मुहर ग्रामसभा से अनुमोदित सूची के बाद अपीलीय समिति शिकायतों और आपत्तियों की जांच करेगी. इसके बाद 31 अक्टूबर तक अंतिम प्राथमिकता सूची का अनुमोदन किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और उपवििकास आयुक्तों को पत्र भेजा है. 1.04 करोड़ में करीब 40 फीसदी नाम हटने की संभावना ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 20 लाख 44 हजार 427 ग्रामीणों ने खुद को आवास पाने के योग्य बताते हुए स्वयं दावा किया है. वहीं 84 लाख 46 हजार 316 लाभुकों ने विभागीय सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से आवास योजना के लिए अपनी पात्रता बतायी है. अधिकारियों के अनुसार जांच और पात्रता की शर्तों के आधार पर इनमें से करीब 40 फीसदी नाम हटने की संभावना है. पक्का मकान और दो से अधिक कमरे होने पर लाभ नहीं अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए कई कड़े मापदंड लागू किये गये हैं. जिन परिवारों के पास पक्की छत या पक्की दीवारों वाला मकान है अथवा दो से अधिक कमरों का मकान है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन और मशीनी कृषि उपकरण रखने वाले परिवार भी पात्र नहीं होंगे. 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वालों को भी बाहर किया जायेगा योजना के तहत ऐसे परिवार भी पात्र नहीं होंगे, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक है. परिवार में कोई सदस्य आयकर या व्यवसाय कर देता है तो भी लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा 50 हजार रुपये या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार और सरकारी नौकरी वाले परिवारों को भी सूची से बाहर रखा जायेगा. जमीन की सीमा भी तय की गयी पात्रता की जांच में जमीन को भी आधार बनाया गया है. जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या पांच एकड़ से अधिक अशिरंचित भूमि है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची में शामिल नहीं किया जायेगा. इन परिवारों को प्राथमिकता देने की तैयारी प्रतीक्षा सूची में कमजोर और वंचित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी. इसमें दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, महिला प्रधान परिवार जिनमें कोई वयस्क पुरुष नहीं है, आश्रयहीन परिवार, भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, बंधुआ मजदूर, आदिम जनजातीय समूह और गंभीर बीमारी से प्रभावित परिवार शामिल हैं. हर जिले में बनेगी तीन सदस्यीय अपीलीय समिति लाभुकों की शिकायतों और संभावित धांधली की रोकथाम के लिए हर जिले में तीन सदस्यीय जिला स्तरीय अपीलीय समिति गठित की जायेगी. 15 सितंबर तक समिति के गठन का लक्ष्य रखा गया है.

भरत तिवारी की मौत के बाद पहली बार घर पहुंचे डीएम-एसपी, आधे घंटे की बातचीत में परिवार ने रखी ये मांगें

पटना (एजेंसी) : पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के बाद उनके पैतृक गांव बिलौटी में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. भोजपुर के डीएम और एसपी ने तिवारी के परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं, जिसमें न्याय, स्मारक निर्माण और विस्थापितों की मदद की मांग प्रमुख है. 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के बाद चर्चा में आए बिलौटी गांव में शनिवार को एशासनिक हलचल देखने को मिली. भोजपुर के डीएम मनीष कुमार मीना और एसपी अभिषेक दक्षित पहली बार भरत तिवारी के पैतृक घर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने करीब आधे घंटे तक भरत के माता-पिता और अन्य परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. परिवार ने न्याय और स्मारक निर्माण की मांग के दौरान भरत तिवारी के परिजनों ने उनकी मौत



के मामले में न्याय की मांग दोहराई. परिवार ने भरत की याद में स्मारक निर्माण कराने के साथ आवास परिसर और आसपास मिट्टी भराई कराने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी. गंगा कदम से विस्थापित परिवारों का मुद्दा भी उठा परिजनों ने गंगा कटान से प्रभावित बिलौटी के विस्थापित परिवारों की समस्याओं को भी

अधिकारियों के सामने रखा. परिवार के अनुसार, कई बाढ़पीड़ित अब तक सरकारी सहायता की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं. विस्थापित इलाके में घर, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया. पानी कम होने के बाद सड़क और मिट्टी भराई का भरोसा परिवार के मुताबिक, डीएम मनीष

कुमार मीना ने भरोसा दिया कि बाढ़ का पानी कम होने और क्षेत्र के सूखने के बाद जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. विस्थापित इलाके में मिट्टी भराई कर पक्की सड़क बनाने और घरों के लिए सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई. डीएम ने संबंधित एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. भरत तिवारी के घर पर पुलिस गार्ड तैनात परिजनों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए भरत तिवारी के घर पर पुलिस गार्ड तैनात किया गया है. अधिकारियों ने परिवार को सरकार की ओर से घोषित प्रावधानों के तहत अनुक्रंणा पर नौकरी और अन्य सरकारी सहायता की प्रक्रिया को जांच आयोग भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद मामला काफी चर्चित हुआ था. घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है.

जाने की शिकायत भी डीएम-एसपी के सामने रखी. शिकायत पर शाहपुर थानाध्यक्ष को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. सीओ को कागजी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने का निर्देश मौके पर डीएम ने सीओ को बुलाकर परिवार से जुड़ी कागजी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. स्मारक निर्माण, परिसर में मिट्टी भराई और सरकारी सहायता से र्वंचित बाढ़पीड़ितों के नाम सूची में जोड़ने की मांग पर भी प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया. भरत तिवारी की मौत के बाद गठित हुआ न्यायिक जांच आयोग भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद मामला काफी चर्चित हुआ था. घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है.

बिहार के 1.04 करोड़ लोगों को मिलेगा पीएम आवास, इन लोगों का कट सकता है नाम, जानिए क्यों नहीं मिलेगा लाभ

पटना (एजेंसी) बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई है. 1 करोड़ से अधिक लोगों की सूची तैयार है, लेकिन 40% लोगों के नाम कटने की संभावना है. अपात्रता के कड़े मापदंडों और अनुमोदन प्रक्रिया को समझें. बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत घर पाने वाले संभावित लाभुकों की प्रक्रिया आगे बढ़ गयी है. राज्य के 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार 743 लाभुकों को योजना का लाभ देने के लिए आवास सॉफ्टवेयर के जरिए प्रारूप सूची तैयार की गयी है. 11 सितंबर को 'डिलीशन मॉड्यूल' का काम पूरा कर सूची जिला लॉगिन में भेज दी गयी है. जबकि 40 फीसदी लाभुकों के नाम कटने के भी आसार हैं. 30 सितंबर तक ग्रामसभा से सूची

का अनुमोदन तैयार प्रारूप सूची को अब संबंधित ग्रामसभा के सामने रखा जायेगा. अधिकतम 20 दिनों के भीतर यानी 30 सितंबर तक ग्रामसभा से सूची का अनुमोदन कर उसे प्रखंड कार्यालय को वापस भेजना अनिवार्य होगा. इसके लिए 27 सितंबर को पंचायत विकास दिवस के अवसर पर विशेष ग्रामसभा आयोजित कर सूची के अनुमोदन की तैयारी है. समय पर ग्रामसभा नहीं हुई तो सूची स्वतः अनुमोदित निर्धारित समय-सीमा में यदि किसी पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन नहीं हो पाता है, तो संबंधित सूची स्वतः अनुमोदित मानी जायेगी. साथ ही समय पर ग्रामसभा नहीं कराने वाले संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. 31 अक्टूबर तक अंतिम

प्राथमिकता सूची पर मुहर ग्रामसभा से अनुमोदित सूची के बाद अपीलीय समिति शिकायतों और आपत्तियों की जांच करेगी. इसके बाद 31 अक्टूबर तक अंतिम प्राथमिकता सूची का अनुमोदन किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और उपवििकास आयुक्तों को पत्र भे है. 1.04 करोड़ में करीब 40 फीसदी नाम हटने की संभावना ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 20 लाख 44 हजार 427 ग्रामीणों ने खुद को आवास पाने के योग्य बताते हुए स्वयं दावा किया है. वहीं 84 लाख 46 हजार 316 लाभुकों ने विभागीय सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से आवास योजना के लिए अपनी पात्रता बतायी है



बना हुआ है कि अपराधियों को आखिर कैसे पता चला कि मणिभूषण और ननकी रात में घर की छत पर सोते हैं. बताया जाता है कि दोनों छत पर सो रहे थे. इसी दौरान अपराधी वहां पहुंचे और गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी.वारदात के बाद कमरों को बाहर

से कर दिया गया था बंद वारदात के बाद घर में मौजूद अन्य लोगों के कमरों को बाहर से बंद कर दिया गया था. इससे पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि अपराधियों को घर की बनावट, परिवार के सदस्यों की मौजूदगी और रात में दोनों के छत पर सोने की जानकारी पहले से थी या नहीं. पहले रेकी हुई थी या किसी ने दी थी जानकारी? जांच का अहम सवाल यह भी है कि क्या अपराधियों ने पहले रेकी की थी या किसी व्यक्ति से उन्हें घर की गतिविधियों की जानकारी मिली थी. हालांकि, अभी तक पुलिस ने किसी व्यक्ति को खुशबू अथवा

साजिश में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है. ऐसे में किसी परिचित या स्थानीय व्यक्ति पर संदेह जताना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा. मृतकों के संपर्क में रहने वालों से जुटायी जा रही जानकारी पुलिस मृतकों के संपर्क में रहने वाले लोगों, घटना से पहले की गतिविधियों और आसपास की आवाजों की जानकारी जुटा रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों के आने और भागने के रास्ते की भी पड़ताल की जा रही है. अचानक वारदात हुई या पहले से तैयार थी योजना? पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है

